जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 47 संख्याः 183 प्रभात | बीकानेर, रविवार 25 जनवरी, 2026 | डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 | पृष्ठ 8 | मूल्य 2.50 रु.

राहुल भी उस सुविधा के आरामदेह जाल में फंस गये हैं, जिसमें सोनिया गांधी फंसी थीं

सोनिया गांधी सदा इस बात से बचती थीं , कि पार्टी अपनी हार के कारणों पर गंभीरता से बहस करे, और यह तय हो कि, हार के लिये जिम्मेवार कौन था

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जनवरी। लगातार हारों के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व अब तक हार की समीक्षा और जिम्मेदारी तय करने के मुद्दे पर उलझा हुआ है। पूर्व में पार्टी में इन हारों के लिए "इनाम और सज़ा" की बात हुई थी, पर कोई जवाबदेही तय नहीं की गई।

राहुल गांधी उस समय स्पष्ट थे कि यह सिस्टम जारी नहीं रह सकता और उन्होंने पूरा सिस्टम बदलने का वादा किया था। लेकिन अब राहुल और उनके नए सलाहकार, जो सोनिया गांधी की कोर टीम और पुराने सलाहकारों से बेहतर बताए जा रहे हैं, उसी जाल और उसी स्तर के आराम में फंस गए हैं।

एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, राहुल भी अब उसी आरामदायक स्तर पर हैं, जिस पर सोनिया गांधी थीं, जहाँ वे कुछ नहीं करके और बहुत सारी पराजयों के लिए किसी को जिम्मेवारी और जवाबदेही नहीं देकर खुश हैं।

दिलचस्प बात है कि सोनिया गांधी के समय पार्टी में बहुत ज्यादा अनुभवी और प्रभावशाली नेता मौजूद थे, जो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- उस समय राहुल गांधी ने पुरजोर ढंग से कहा था, यह स्थिति अब नहीं चलेगी, तथा वे पूरी व्यवस्था बदल देंगे।
- राहुल का यह भी मानना है कि उनके सलाहकारों का समूह, सोनिया गांधी के सलाहकारों की कोर टीम से बेहतर है।
- पर, राहुल गांधी भी अब उस आराम के आदी हो गए हैं, जिसमें उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता और किसी पर भी हार की जिम्मेवारी तय करके दंड या पारितोषिक नहीं देना पड़ता।
- और, राहुल ने पार्टी को चलाने की जिम्मेवारी अपने खास लोगों पर छोड़ रखी है। पर, पार्टी के लिए चिंता का विषय यह है कि, इन "खास लोगों" को राजनीतिक अनुभव नहीं, और ना ही उन्हें समझ है, आज की राजनीति के कड़े संघर्ष को गहराई से जांचने की।
- जबकि दूसरी ओर पार्टी का मुकाबला भाजपा व संघ के चुस्त व दुरुस्त संगठन से है। सोनिया जी के समय के, पुराने वरिष्ठ सलाहकार अब नहीं रहे, जिन्हें अनुभव था राजनीति निर्णय लेने का सामर्थ्य भी दे रखा था पार्टी में।

जो मुद्दे हैं उन्हें पार्टी नेतृत्व के साथ उठाना है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जनवरी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल विधानसभा चुनावों पर चर्चा के लिए दिल्ली में हुई कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक में अपनी अनुपस्थिति को लेकर सार्वजनिक अटकलों में पड़ने से साफ़ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही पर्याप्त चर्चा हो चुकी है और यदि कोई मुद्दा होगा भी, तो वह सीधे पार्टी नेतृत्व के समक्ष उठाया जाएगा।

केरल लिटरेचर फेस्टिवल में बोलते हुए तिरुवनंतपुरम से चार बार के सांसद थरूर ने स्पष्ट किया कि वे पार्टी के अन्दरुनी मामलों को उठाने के लिए किसी सार्वजनिक मंच का उपयोग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, "मैं यहां कोई राजनीतिक घोषणा करने नहीं आया हूं। यह एक साहित्यिक उत्सव है। ये ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें मुझे अपनी पार्टी के नेतृत्व

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- केरल के कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में हुई मीटिंग में नहीं आने पर थरूर ने सफाई दी कि वे पार्टी के मंच पर ही इस बारे में बात करेंगे किसी और मंच पर नहीं।

वंदे मातरम के दौरान भी सीधे खड़ा होना पड़ेगा

केन्द्र सरकार राष्ट्र गीत वंदे मातरम को राष्ट्र गान जन गण मन जैसा दर्जा देने की तैयारी में है

- श्रीनंद झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 24 जनवरी। क्या भारत के राष्ट्र गीत को राष्ट्रीय गान के समान दर्जा और सम्मान मिलना चाहिए?

इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्" को राष्ट्र गान के समान सम्मान सुनिश्चित करने के लिए एक विधिवत प्रस्ताव तैयार करना था।

वर्तमान समय में, दोनों गीतों के लिए कानूनी और अनिवार्य प्रोटोकॉल में एक महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है। उदाहरण के लिए, जब राष्ट्र गान बजाया जाता है तो खड़ा होना अनिवार्य है और ऐसा न करने या इनकार करने पर "प्रीवेन्शन ऑफ इन्सल्ट्स नैशनल ऑनर एक्ट, 1971" के तहत दंड का प्रावधान है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय गीत के बजने पर खड़ा होना अनिवार्य बनाने वाला कोई लिखित नियम या कानूनी बाध्यता फिलहाल मौजूद नहीं है।

वंदे मातरम् पर भाजपा सरकार का नया जोर आगामी विधानसभा चुनावों, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, हिंदू मतों के एकीकरण की पार्टी की राजनीतिक रणनीति के अनुरूप देखा जा रहा है। इस गीत को लेकर ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक व्याख्याओं से जुड़े विवाद लंबे समय से रहे हैं। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत उनके उपन्यास "आनंद मठ" से लिया गया है और इसमें कुल छह अंतरे (स्टैन्ज़ा) हैं, जिनमें हिंदू देवी की छवियां शामिल हैं। पार्टी के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को ध्यान में रखते हुए, कांग्रेस कार्यसमिति ने 1937 की बैठक में केवल पहले दो अंतरों के प्रयोग का निर्णय लिया था, क्योंकि बाद के अंतरे मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों को अलग-थलग कर सकते थे।

यह विवाद पिछले वर्ष गीत की 150वीं वर्षगांठ पर फिर से उभरा, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तर्क दिया कि कांग्रेस द्वारा गीत को संक्षिप्त किए जाने का देश के विभाजन में योगदान रहा। कांग्रेस ने इस निर्णय का बचाव करते हुए इसे सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम बताया। कुछ मुस्लिम विद्वानों, जैसे मौलाना अरशद मदनी, ने कहा है कि वे राष्ट्रीय गीत का सम्मान करते हैं, लेकिन, एकेश्वरवाद से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के कारण, इसके सामूहिक गायन में भाग नहीं ले सकते।

1905-08 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान "वंदे मातरम्" एक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- राष्ट्र गान जन गण मन जब बजाया जा रहा हो तब खड़े होना अनिवार्य है और इसके लिए प्रिवैंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट बनाया गया है, पर वंदे मातरम में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। केन्द्र सरकार वंदे मातरम को भी राष्ट्र गान, जन गण मन जैसा दर्जा देने की तैयारी में है।
- इस सम्बध में गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। चर्चा है कि भाजपा सरकार बंगाल चुनावों के मद्देनजर वंदे मातरम के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है और इस आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण की उम्मीद कर रही है।

पुरानों पर संदेह है और नयों पर भरोसा नहीं हो रहा

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेना के उच्च पदों पर तैनात अपने पुराने साथियों को हटा रहे हैं, पर उनकी जगह नई नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जनवरी। चीन ने अपने सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को हटा दिया है। यह कदम राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा चलाए जा रहे उस कठोर अभियान का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें उन सभी लोगों को हटाया जा रहा है, जो राजनीतिक रूप से या सत्ता के लिहाज से उनके संभावित प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं।

जनरल झांग योउशिया, जो अब तक चीन के अत्यंत शक्तिशाली सेंट्रल मिलिट्री कमीशन (सी.एम.सी.) के उपाध्यक्ष थे, को हटाए जाने के बाद इस सात सदस्यीय शीर्ष सैन्य संस्था में अब केवल एक ही अन्य सदस्य बचा है। यही संस्था चीन की विशाल सेना को नियंत्रित करती है।

शी जिनपिंग ने एक के बाद एक सबसे ताकतवर सैन्य अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। लगातार चल रही इन कार्रवाहियों में कई शीर्ष सैन्य कमांडरों को पद से हटाकर जेल या हिरासत शिविरों में भेजा गया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- हाल ही में शी ने अपने पुराने साथी और बेहद वफादार रहे जनरल झांग को पद से हटा दिया, वे चीन के सर्वशक्तिमान सैंट्रल मिलिटरी कमिशन के वाइस चेयरमैन थे।
- जनरल झांग और शी की राजनैतिक व सामाजिक पृष्ठभूमि एक जैसी थी इसीलिए जनरल झांग शी के बेहद विश्वासपात्र बन गए। लेकिन शी ने भ्रष्टाचार के संदेह में जनरल झांग को हटा दिया है।
- असल में शी ज़िनपिंग ने चीन की सेना का शुद्धिकरण शुरु किया है, क्योंकि, भारी भ्रष्टाचार की खबरें मिल रही थीं पर इससे सेना के उच्चस्तर पर एक खालीपन सा आ गया है।

थरुर ने कैनडा के प्र.मंत्री की चेतावनी का समर्थन किया

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 24 जनवरी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को सुझाव दिया कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में भारत को कैनडा के प्रधानमंत्री की 'जीवित बने रहने' की अपील से सीख लेनी चाहिए।

उन्होंने कहा, इस सप्ताह दावोस की बर्फीली पृष्ठभूमि में कैनडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ऐसा भाषण

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- थरुर ने कहा, आज विश्व की व्यवस्था जिसकी लाठी उसकी भैंस पर आधारित है, नियम टूटते जा रहे हैं। भारत को भी कैनडा के प्र.मंत्री की चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए।

'10 साल में ए.आई. के उपयोग से भारत की आय में 45 लाख करोड़ रुपये का इजाफा होगा'

जानी मानी कॉरपोरेट सलाहकार व "चारटर्ड एकाउन्टैंट" कम्पनी प्राइस वॉटर हाऊस (पी.डब्ल्यु.सी.) का यह आंकलन भारत के लिये बहुत उत्साह वर्धक है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जनवरी। प्राइस वॉटरहाउस कूपर्स (पी.डब्ल्यु.सी.) इंडिया ने एक व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई) फ्रेमवर्क पेश किया है, जिसका अनुमान है कि यह टैक्नॉलजी, सन् 2035 तक, पांच मुख्य सेक्टर्स में, नॉमिनल कीमतों पर भारत के लिए लगभग 550 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 45 लाख करोड़ रुपये) का अतिरिक्त आर्थिक मूल्य पैदा कर सकती है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, यह देखते हुए कि खर्च के मामले में भारत के सालाना बजट का आकार 50 लाख करोड़ रुपये है।

आंकड़ों से आगे, फर्म का तर्क है कि भारत के पास न केवल बड़े पैमाने पर ए.आई को लागू करने का, बल्कि "इन्क्लूसिव ए.आई." का एक विश्व स्तर पर विशिष्ट मॉडल बनाने का दुर्लभ अवसर है, एक ऐसा मॉडल जो उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ समाज के हर वर्ग पर सकारात्मक असर डाले।

पी.डब्ल्यु.सी. के अनुसार, अनुमानित आर्थिक लाभ का बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, हेल्थकेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज़ और रिटेल से आएगा, ये ऐसे सेक्टर्स हैं, जो मिलकर लाखों भारतीयों को रोज़गार देते हैं और देश के विकास और प्रगति की चुनौती के केन्द्र में हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की पिछली लहरों के विपरीत, जो मुख्य रुप से सेवाओं और शहरी इलाकों तक सीमित थीं, पी.डब्ल्यु.सी. का सुझाव है कि ए.आई. का अगला चरण भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था में गहराई तक प्रवेश कर सकता है।

मैन्युफैक्चरिंग में, ए.आई. आधारित ऑटोमेशन, मशीनों की पहले से खराबी पहचानने की तकनीक और गुणवत्ता सुधार से उत्पादन बढ़ेगा और लागत कम होगी, जिससे भारतीय फर्मों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी, भले ही सप्लाई चेन अधिक खंडित और संरक्षणवादी हो जाएं। कृषि क्षेत्र में ए.आई. आधारित सलाह प्रणाली, जिसमें सैटेलाइट डेटा, मौसम की जानकारी और स्थानीय मिट्टी की जानकारी शामिल होगी, खेती की पैदावार बढ़ा सकती हैं, इनपुट की बर्बादी कम कर सकती हैं और छोटे किसानों के लिए आय को स्थिर कर सकती हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक कमजोरी है।

हेल्थकेयर को एक और बड़ा लाभार्थी माना जा रहा है। पी.डब्ल्यु.सी. भारत में डॉक्टरों और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की पुरानी कमी को दूर करने के तरीके के रूप में ए.आई. आधारित जांच प्रणाली, मरीजों की प्राथमिक जांच और दूरस्थ इलाज मॉडल भारत में डॉक्टरों और स्वास्थ्य ढांचे की कमी को कम करने में मदद कर सकती है। यदि जिम्मेदारी से लागू

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- इस आंकलन का पूरा महत्व समझने के लिये यह जानना जरुरी है, कि देश के बजट में खर्चे का आंकड़ा वर्तमान में कुल 50 लाख करोड़ है।

गणतंत्र दिवस परेडः पहली बार दो विदेशी नेता चीफ गैस्ट होंगे

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 24 जनवरी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फ़ॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्टा 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाली भारत की 77वीं गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि होंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बतौर चीफ गैस्ट यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपियन काउन्सिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को आमंत्रित किया है।

ट्रम्प के "गाज़ा स्ट्रिप प्लान" ने देश के पुराने अमेरिका - इज़रायल विशेष सम्बंधों को खतरे में डाल दिया है?

कतर व टर्की को अमेरिका उस बोर्ड का सदस्य बनाने को आमादा है, जो "गाज़ा-स्ट्रिप" का पुनर्निर्माण करेगा। पर, इज़रायल इनकी सदस्यता किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जनवरी। वॉशिंगटन और यरुशलम के बीच तनाव अब खुलकर सामने आ गया है। इज़रायल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्धोत्तर ग़ाज़ा के लिए वाइट हाउस द्वारा प्रस्तावित बोर्ड को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया है, लेकिन अमेरिका इज़रायल की आपत्तियों के बावजूद इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता है। जो मामला पहले कूटनीतिक बैकचैनलों के ज़रिये चुपचाप सुलझाया जा सकता था, वह अब लंबे समय से सहयोगी रहे दो देशों के बीच एक दुर्लभ सार्वजनिक टकराव में बदल गया है। इससे न केवल अमेरिका-इज़रायल संबंधों की गहरी दरारें उजागर हुई हैं, बल्कि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के तहत अमेरिका के गठबंधनों को लेकर व्यापक सोच भी सामने आई है।

इस विवाद के केन्द्र में युद्ध के बाद ग़ाज़ा के प्रशासन के लिए वॉशिंगटन द्वारा हाल ही में प्रस्तुत ढांचा है। इस प्रस्ताव में एक निगरानी बोर्ड शामिल है, जिसके पास पुनर्निर्माण, सुरक्षा समन्वय और नागरिक शासन की ज़िम्मेदारी संभालने वाला एक शक्तिशाली कार्यकारी अंग होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यकारी निकाय में क़तर और तुर्की को शामिल किया गया है-दो ऐसे देश जिन पर इज़रायल गहरा संदेह करता है। इज़रायल लंबे समय से क़तर पर हमास से संबंध रखने का आरोप लगाता रहा है, जबकि राष्ट्रपति तैयप एर्दोआन के नेतृत्व में तुर्की ग़ाज़ा युद्ध शुरू होने के बाद से नेतन्याहू के सबसे मुखर आलोचकों में शामिल रहा है।

इज़रायल की प्रतिक्रिया त्वरित और तीखी रही। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि इस योजना पर इज़रायल से कोई समन्वय नहीं किया गया और यह "इज़रायल की घोषित नीतिगत प्राथमिकताओं के सीधे खिलाफ है", विशेषकर युद्ध के बाद ग़ाज़ा में शत्रुतापूर्ण क्षेत्रीय शक्तियों के प्रभाव को रोकने के उसके लक्ष्य के संदर्भ में। इज़रायल के लिए क़तर और तुर्की की भागीदारी कोई तकनीकी विवरण नहीं, बल्कि एक खतरे की रेखा है-क्योंकि यह उस युद्धोत्तर ढांचे का संकेत देती है जिसे इज़रायल उन ताकतों द्वारा आकार दिया हुआ मानता है जो हमास-समर्थित नेटवर्क को निष्प्रभावी करने के बजाय वैधता प्रदान करेंगी।

हालांकि, लोगों को इज़रायल की अस्वीकृति से नहीं, बल्कि वॉशिंगटन की प्रतिक्रिया से भी हैरानी हुई है। वरिष्ठ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- इज़रायल का सोच है कि कतर के "हमास" से अच्छे सम्बंध हैं, और टर्की के राष्ट्रपति एरडोगन, इस समय इज़रायल व प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रबलतम आलोचक हैं, टर्की को इस्लामिक देशों का नेता बनाने के प्रयास में हैं।
- इज़रायल की आपत्तियों से भी ज्यादा चौंकाने वाली है, इस संदर्भ में अमेरिका की प्रतिक्रिया। अमेरिका ने इज़रायल को साफ कह दिया, उसकी आपत्तियों के बावजूद वह कतर व टर्की को बोर्ड का सदस्य बनाएगा, क्योंकि उस पर (अमेरिका पर) भारी अन्तर्राष्ट्रीय दबाव है, कि "गाज़ा स्ट्रिप" के पुनर्निर्माण को आगे बढ़ाये।
- अमेरिका की प्रतिक्रिया ने अन्तर्राष्ट्रीय "डिप्लोमैसी" (कूटनीति में) उसका सोच उजागर कर दिया है कि वह तत्कालिक लाभ (ट्रांज़ैक्शनल अप्रोच) के पक्ष में है, न कि दूरगामी मित्रता व नजदीकियों में।
- यह सोच बहुत चौंकाने वाला तो है ही इसने अन्य देशों को भी चौकन्ना कर दिया है, अमेरिका के वादों के प्रति।

वर्षा के बाद भी दिल्ली में प्रदूषण नहीं घटा

नयी दिल्ली, 24 जनवरी। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को हुई बारिश और तापमान में गिरावट के बावजूद शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब श्रेणी में बनी रही।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शहर के कुछ इलाकों में प्रदूषण का स्तर अब भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है।

सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार सुबह दिल्ली का औसत एक्यूआई खराब श्रेणी में रहा, जिसमें सूक्ष्म कणों (पीएम 2.5) की अधिकता देखी गई।

विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के कारण तापमान में तो कमी आई है लेकिन प्रदूषण के स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं दिखा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- शहर के कुछ इलाकों में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में रहा।

CMYK